

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

बनाम

श्रीकांत ट्रांसपोर्ट

मई 14, 1999

[वी.एन. खरे और उमेश सी. बनर्जी, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता अधिनियम 1940: धारा 20-अपवादित खंड-सरकारी अनुबंध-वादी द्वारा अपने अधिकारी के माध्यम से अपवादित विषय के न्यायनिर्णयन के अधिकार का सकारात्मक परित्याग-मध्यस्थ को अपवादित खंड की विषय वस्तु का संदर्भ-अभिनिर्धारित: सामान्य परिस्थितियों में अपवादित खंड पर विचार नहीं किया जाता है-लेकिन अधिकार के स्पष्ट परित्याग को देखते हुए ऐसा मार्ग सही है।

उत्तरदाता ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक वाद दायर किया। विचारण न्यायालय ने वाद के तीन मुख्य दावों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया, लेकिन चौथे दावे को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी विषय वस्तु समझौते के खंड 12 [अपवादित विषय] के अंतर्गत आती थी। विचारण न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के वाद के चौथे दावे की विषय वस्तु के संबंध में एक वाद दायर करके दीवानी कार्यवाही शुरू की। उत्तरदाता ने इस आधार पर इस पर आपत्ति जताई कि चूंकि वादी ने मामले को अपने स्वयं के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा तय कराने के बजाय दीवानी न्यायालय की न्यायनिर्णयन प्रक्रिया का सहारा लिया है, इसलिए अपीलकर्ता के वाद से जुड़े मुद्दे को भी, जिसका उत्तरदाता के वाद के तीन मुद्दों से सीधा संबंध है, मध्यस्थ को भेजा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता के वाद में

विवादित सभी मुद्दों को मध्यस्थ को यह मानते हुए भेज दिया कि अपीलकर्ता के वाद का उत्तरदाता के वाद के चौथे दावे के साथ आंतरिक संबंध था। अतः यह अपील प्रस्तुत है।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. सामान्य परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा अपवादित विषयों से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं किया जाता है। मामले में तथ्यात्मक स्थिति के कारण, उच्च न्यायालय के पास इस तरह की कार्रवाई का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, वह भी अधिकार के स्पष्ट परित्याग के कारण। घटनाओं के सामान्य क्रम में यदि संबंधित पक्षों के बीच अनुबंध में विशेष खंड उपलब्ध नहीं था, तो मध्यस्थता खंड के दायरे और परिधि के कारण संपूर्ण विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता था। लेकिन यदि यह खंड 12 को शामिल करने के तथ्य और खंड 12 के अंतर्गत आने वाले दावे को वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक के अलावा किसी अन्य फोरम द्वारा न्यायनिर्णयन कराने के निर्णय के कारण इसके बाद के परित्याग के कारण है, तो यह न्यायालय उच्च न्यायालय से सहमत है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए दीवानी वाद का विषय होने के नाते चौथे विवाद को भी मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। [706-एफ-एच]

1.2. इसके अलावा, जहाँ तक अपवादित विषयों के न्यायनिर्णयन का संबंध है, अपीलकर्ता निगम द्वारा अधिकार का एक सकारात्मक त्याग या परित्याग प्रतीत होता है क्योंकि निगम स्वयं इसे दीवानी न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णित कराना चाहता था। [704-एच; 705-ए]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1994 की दीवानी अपील संख्या (ओं) 1582-83।

1990 की ओ.एस. संख्या 39-40 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 4.10.93 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए वाई. प्रभाकर राव।

उत्तरदाता के लिए शंभू प्रसाद सिंह, मेसर्स अर्पुथम और अरुणा एंड कंपनी।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

बनर्जी, न्यायमूर्ति। विशेष अनुमति प्रदान करने के माध्यम से ये अपीलें एक सरकारी अनुबंध में मध्यस्थता खंड के मुकाबले सामान्य 'अपवादित खंड' के प्रभाव से संबंधित हैं। यद्यपि यह सत्य है और जैसा कि तर्क दिया गया है, कि मध्यस्थों को मध्यस्थता करने का अधिकार समझौते से प्राप्त होता है, लेकिन आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने समझौते में 'अपवादित मामलों' का मध्यस्थों द्वारा न्यायनिर्णयन का निर्देश देना उचित समझा और इसलिए इस न्यायालय के समक्ष ये अपीलें प्रस्तुत हैं।

आरंभ में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि सामान्य सरकारी अनुबंधों में, जिनका संदर्भ इसके तुरंत बाद दिया जाएगा, मध्यस्थता के दायरे से कुछ मामलों का बहिष्करण होता है और आमतौर पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को उसी का न्यायनिर्णयन करने का प्राधिकार और शक्ति दी जाती है। खंड स्वयं अभिलेख करता है कि वरिष्ठ अधिकारी का निर्णय, न्यायनिर्णायक होने के नाते, अंतिम होगा और पक्षों के बीच बाध्यकारी होगा - यही सरकारी या सरकारी अभिकरणों के अनुबंध में लोकप्रिय रूप से 'अपवादित विषय' के रूप में जाना जाता है।

'अपवादित मामलों' में स्पष्ट रूप से, जैसा कि पक्ष सहमत हुए, किसी और न्यायनिर्णयन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि समझौता स्वयं एक नामित न्यायनिर्णायक प्रदान करता है; उसी के प्रति सहमति स्पष्ट रूप से पक्षों द्वारा अनुबंध की शर्तों की असंदिग्ध स्वीकृति के कारण मानी जाती है और यही वह जगह है जहाँ न्यायालयों ने इससे उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में कमी पाई है और यह एक सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि अपवादित मामलों के दायरे में उत्पन्न होने वाले दावों की स्थिति में, न्यायालय के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना किसी भी

मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता; पक्षों ने स्वयं इन मामलों के संबंध में एक विशेष अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन कराने का निर्णय लिया है: हालांकि ये अपवाद क्या हैं, यह तथ्य के प्रश्न हैं और आमतौर पर अनुबंध दस्तावेजों में उल्लिखित होते हैं और समझौते का हिस्सा बनते हैं; इस प्रकार इन विशिष्ट मामलों के न्यायनिर्णयन के मामले में कोई अस्पष्टता नहीं है और समझौते में इन्हें अपवादित मामलों के रूप में जाना जाता है।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने, हालांकि, वास्तव में, उन मामलों को जो समझौते के संदर्भ में अपवादित मामलों के भीतर आते हैं, अन्य मध्यस्थता योग्य विवादों के साथ मध्यस्थ को संदर्भित किया है। इस मोड़ पर मध्यस्थता खंड पर ध्यान देना सुविधाजनक होगा।

"इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से छूने वाले या संबंधित सभी विवाद और मतभेद (किसी भी ऐसे मामले को छोड़कर जिसका निर्णय अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है) एफसीआई के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति की एकल मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाएंगे। इस तरह की किसी भी नियुक्ति पर यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति निगम का कर्मचारी है या था, कि उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे अनुबंध संबंधित है और निगम के ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे। ऐसे मध्यस्थता का बोर्ड अंतिम होगा और इस अनुबंध के पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह इस अनुबंध की एक शर्त है कि यदि ऐसे मध्यस्थ, जिसे मूल रूप से मामला भेजा गया है, का स्थानांतरण हो जाता है या वह अपना कार्यालय खाली कर देता है या किन्हीं कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे स्थानांतरण, कार्यालय खाली करने या कार्य करने में असमर्थता के समय एफसीआई के प्रबंधक/प्रबंध निदेशक

किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा। यह भी इस अनुबंध की एक शर्त है कि प्रबंध निदेशक द्वारा उपरोक्त रूप से नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से यह संभव नहीं है तो मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा।

यह अनुबंध की एक शर्त है कि इस खंड के तहत मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रबंध निदेशक से अनुरोध करते समय मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने वाले विवादों और/या मतभेदों के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक विवाद/मतभेद के संबंध में दावा की गई राशि को निर्दिष्ट करेगा।

आगे यह भी प्रावधान है कि अनुबंध के तहत ठेकेदारों के किसी भी दावे के संबंध में मध्यस्थता की कोई भी मांग लिखित रूप में होगी और यदि अनुबंध पहले समाप्त हो जाता है तो ठेकेदार के पूर्ण होने (या अवधि समाप्त होने) की समाप्ति की दिनांक से या अनुबंध की समाप्ति की दिनांक से एक वर्ष के भीतर की जाएगी और जहां उस अवधि के भीतर ऐसी मांग नहीं की जाती है, तो ठेकेदारों के दावे मुक्त कर दिए जाएंगे और इन दावों के संबंध में अनुबंध के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिए जाएंगे। इसमें आगे यह प्रावधान है कि मध्यस्थ, समय-समय पर, पक्षों की सहमति से पंचाट बनाने और प्रकाशित करने का समय बढ़ा सकता है।

उन सभी मामलों में जहां विवादित दावा 25,000 रुपये और उससे अधिक है, मध्यस्थ अपने पंचाट के कारणों को दर्ज करेगा।

पूर्वोक्त के अधीन, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। मध्यस्थता की और उसके संबंध में लागत मध्यस्थ के विवेक पर होगी जो अपने पंचाट में इसके लिए उपयुक्त प्रावधान कर सकता है।"

अब प्रासंगिक तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच कुछ विवादों के कारण यहाँ उत्तरदाता ने न्यायालय में मध्यस्थता समझौता दाखिल करने के उद्देश्य से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत वर्ष 1982 का वाद संख्या 304 दायर किया। संयोगवश, स्मरण रहे कि वाद में दायर वादपत्र में यहाँ उत्तरदाता ने चार अलग-अलग दावों को शामिल किया है, जिनमें से चौथा दावा समझौते के खंड XII के संदर्भ में अपवादित मामलों से संबंधित है। वादपत्र में दर्ज किए गए दावे निम्नानुसार हैं:

- (ए) "क्या वादी विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं या क्या प्रतिवादी, प्रतिवादियों के अधिकारियों की चूक और कृत्यों और रेलवे माल गोदामों में प्रचलित असामान्य स्थितियों के कारण अर्जित विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं?"
- (बी) क्या वादी प्रतिवादियों द्वारा बाहर से प्राप्त पानी की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं?"
- (सी) क्या प्रतिवादी, एक्सप्रेस क्लियरिंग एजेंसी या किसी अन्य अनुबंध के संबंध में कथित तौर पर देय राशि को, इस वर्तमान अनुबंध में देय राशियों में से वादी से वसूलने के हकदार हैं?"
- (डी) क्या प्रतिवादी, जून से अगस्त 1979 तक मद्रास से रोनिगुंटा तक चावल के परिवहन के संबंध में वादी को 70,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?"

यह दावा (डी) का ही समावेश है जिस पर यहाँ अपीलकर्ता द्वारा आपत्ति की गई है और विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश ने समझौते के खंड 12 के अंतर्गत आने के कारण इसे शामिल करने से इनकार कर दिया। चूँकि यह मुद्दा इस तरह के बहिष्करण से संबंधित है, इसलिए समझौते के खंड 12 पर ध्यान देना भी सुविधाजनक है, खंड 12 निम्नानुसार है:

"ठेकेदारों की ऐसी विफलता और निगम को हुए नुकसान आदि के लिए उनके दायित्व के संबंध में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक के निर्णय अंतिम होंगे और ठेकेदारों पर बाध्यकारी होंगे।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि आगे दर्शाती है कि विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश के बाद मामले को अपीलीय न्यायालय में ले जाया गया जहाँ रोक के लिए एक आवेदन पर यहाँ उत्तरदाता ने रोक का आदेश प्राप्त किया है। संयोगवश, धारा 20 मामले के लंबित रहने के दौरान, वाद पर रोक लगाने के लिए धारा 34 के तहत एक आवेदन भी था; हालांकि धारा 34 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था, यद्यपि धारा 20 के तहत वाद को पूरी तरह से आदेशित नहीं किया गया था जैसा कि न्यायालय के समक्ष अभिवचन और प्रार्थना की गई थी। जो भी हो, जब मामला अपीलीय न्यायालय के समक्ष आया, तो अपीलीय न्यायालय ने आदेश के संचालन पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए व्यादेश का एक अंतर्वर्ती आदेश पारित किया। हालांकि उसके बाद ही, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर तर्क दिया गया है, कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने में यहाँ उत्तरदाता की लापरवाही, चूक और अकुशल प्रदर्शन के कारण गाड़ी की जब्ती के लिए विलंब शुल्क, घाट-शुल्क और खर्चों का भुगतान करने में यहाँ अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए नुकसान, क्षति और खर्चों की वसूली के लिए एक वाद संस्थित करना उचित समझा। वादपत्र की कंडिका 11 में, वादी ने न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना की:

"(ए) प्रतिवादियों को संयुक्त रूप से और पृथक रूप से वादी को 1,89,775.00 रुपये (एक लाख नवासी हजार सात सौ पचहत्तर रुपये मात्र) की राशि के साथ उक्त राशि पर वादपत्र की दिनांक से वसूली की दिनांक तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देना;

(बी) प्रतिवादियों को वाद का व्यय का भुगतान करने का निर्देश देना; और

(सी) ऐसी और या अन्य राहत पारित करना जो यह माननीय न्यायालय उचित और सही समझे और न्याय प्रदान करे।

महत्वपूर्ण रूप से वादपत्र की कंडिका 8 में, अपीलकर्ता फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उसमें वादी होने के नाते निम्नानुसार कहा:

"8. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तमिलनाडु क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, तमिलनाडु राज्य में निगम के कार्यालयों के प्रमुख के रूप में और निविदा अनुबंध के एक पक्ष के रूप में, निगम को देय राशि की वसूली के लिए वाद दायर करने के हकदार और सक्षम हैं, जैसा कि इस वादपत्र में निर्धारित किया गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मद्रास जिले के जिला प्रबंधक भी निगम के एक प्रधान अधिकारी हैं और वे न केवल अनुबंध और उस पर शामिल कार्य से निकटता से जुड़े हुए हैं, बल्कि वह प्राधिकारी भी हैं जो भुगतान कर रहे हैं, तथा प्रतिवादी ठेकेदार द्वारा कार्य के वास्तविक निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर रहे हैं। जिला प्रबंधक और उनके लोगों को उक्त उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है और उन्हें वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए और उनकी ओर से कार्यवाही संस्थित करने और अभिवचनों और वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है। अनुबंध के खंड III के प्रावधानों के तहत भी यही स्थिति है।

लेकिन खंड 12 के तहत संरक्षित अधिकारों के बारे में क्या, हमने इस संबंध में व्यर्थ ही खोज की: वादपत्र की कंडिका 8 में निहित प्रकथन के अपवाद को छोड़कर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वादपत्र उस बिंदु पर मौन है। इसलिए फूड कॉर्पोरेशन, वास्तव में अपने स्वयं के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से अनुबंध में ही उपलब्ध न्यायनिर्णयन प्रक्रिया पर भरोसा करने के बजाय दीवानी न्यायालय से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,89,775 रुपये की सीमा तक अपने दावे का न्यायनिर्णयन चाहता था। समझौते में जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि न्यायनिर्णयन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जाएगा और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं, और वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक का निर्णय, जैसा कि समझौते में दर्ज किया गया है, पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसलिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से समझौते के उस विशेष खंड पर कोई भरोसा न करने का एक सकारात्मक कार्य है। वास्तव में, तथ्यों की स्थिति के आधार पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता निगम द्वारा अपवादित मामलों के न्यायनिर्णयन के संबंध में किसी अधिकार का सकारात्मक त्याग या परित्याग किया गया है क्योंकि निगम स्वयं इसे दीवानी न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णित कराना चाहता था।

इन अपीलों के समर्थन में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहुत दृढ़ता से तर्क दिया कि वास्तव में, व्यादेश के आदेश के कारण निगम के पास दीवानी वाद शुरू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था और किसी भी स्थिति में यह तर्क दिया गया है कि दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद शुरू करने को मामले में मध्यस्थता समझौते की स्वीकृति के रूप में नहीं पहचाना जाता है और न ही पहचाना जा सकता है; चाहे यह मध्यस्थता की स्वीकृति के बराबर हो या नहीं, हम उस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि घाट-शुल्क दावे के संबंध में निगम के एक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन के अधिकार का परित्याग किया गया

था और इसी परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय की अपीलीय खंड पीठ ने यह निर्देश देने की कृपा की कि 1982 के वाद संख्या सी.एस. 304 में विवादित सभी मुद्दों को मध्यस्थ एल.आर. कोहली को संदर्भित किया जाएगा। उच्च न्यायालय वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 1986 के दीवानी वाद संख्या 368 के विवाद का 1982 के वाद संख्या 304 में यहाँ उत्तरदाता के चौथे दावे के साथ आंतरिक संबंध है। अपीलीय खंड पीठ ने टिप्पणी की:

"चूंकि 1982 के सी.एस. संख्या 304 में पक्षों के बीच विवादों के चार में से तीन विषयों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया है, इसलिए न्यायालय के न्यायनिर्णयन के लिए मध्यस्थ के समक्ष मौजूद अन्य मामले से जुड़े नुकसान के संबंध में एक विषय को बाहर करना वास्तव में अनुचित है। इस तरह की स्थिति में सभी जुड़े तथ्यों की घोषणाओं में टकराव हो सकता है और पक्षों द्वारा क्रमशः न्यायालय और मध्यस्थ के समक्ष लाए गए साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ एक दृष्टिकोण अपना सकता है और न्यायालय दूसरा। इस संबंध में न्यायनिर्णयन को तब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता जब तक कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत कार्यवाही से स्वतंत्र न्यायालय में सभी कार्यवाहियां संपन्न न हो जाएं। ऐसी स्थिति में हमारी राय में उचित और सही आदेश यह है कि 1986 के सी.एस. संख्या 368 का विवाद, जो 1986 के सी.एस. संख्या 304 से जुड़ा एक विषय मात्र है, मध्यस्थ के संदर्भ में शामिल किया जाएगा और तदनुसार उसी मध्यस्थ को संदर्भित किया जाता है जिसके समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भ लंबित है।"

विवादित मामले के तथ्य इस प्रकार विलक्षण रूप से असाधारण हैं क्योंकि एक प्रमुख पक्ष होने के नाते निगम अपने दावों के न्यायनिर्णयन के लिए समझौते के प्रावधानों का सहारा लिए बिना दीवानी वाद संस्थित करना उचित समझता है। दूसरे पक्ष अर्थात् ठेकेदार ने पहले ही

धारा 20 के संदर्भ में एक वाद दायर कर दिया है और जहाँ तक तीन मुख्य विवादों का संबंध है, धारा 20 के प्रावधानों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा संदर्भ के आदेश द्वारा वाद का निपटारा कर दिया गया है। घाट-शुल्क से संबंधित अन्य दावे को विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नकार दिया गया है और हमारे विचार में समझौते के खंड 12 के कारण यह बहुत सही है; इसके बाद यहाँ एक ऐसी स्थिति आती है जो काफी महत्वपूर्ण है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है विलक्षण रूप से असाधारण है: फूड कॉर्पोरेशन स्वयं घाट-शुल्क के दावे के संबंध में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से न्यायनिर्णयन के अपने अधिकार को त्याग देता है और दीवानी न्यायालय में कार्यवाही शुरू करता है। यही वह शुरुआत है जिस पर ठेकेदार द्वारा इस दलील पर आपत्ति की गई है कि चूंकि दीवानी न्यायालयों की न्यायनिर्णयन प्रक्रिया का सहारा प्रमुख पक्ष द्वारा लिया गया है, इसलिए न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस तरह से निर्देश देना चाहिए कि निगम के वाद से संबंधित मुद्दे को भी मध्यस्थता के लिए भेजा जाए क्योंकि इसका उन अन्य तीन मुद्दों से सीधा संबंध है जिन्हें पहले ही मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया जा चुका है। ठेकेदार के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि यदि ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है, तो उस स्थिति में समान क्षेत्र को कवर करने वाले साक्ष्य के दो सेटों की आवश्यकता होगी और इस प्रकार अपीलीय खंड पीठ ने खर्चों को कम करने और पक्षों के बीच विवाद में संपूर्ण मामले के शीघ्र निपटान के मामले में न्याय की आवश्यकता का पालन करने के लिए निगम के वाद में विवादों को भी मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना उचित समझा।

सामान्य परिस्थितियों में, घटनाओं का क्रम जैसा है, यह न्यायालय उन मामलों पर विचार नहीं करता जैसा कि वर्तमान में निपटाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा इंगित किया गया है कि न्याय के उद्देश्य पर विचार करते हुए और न्याय की

आवश्यकता को पूरा करने के लिए मामलों को निपटाया गया है, हम भी यह उचित और सही मानते हैं कि मामले में तथ्यात्मक स्थिति के कारण, उच्च न्यायालय के पास इस तरह की कार्रवाई का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, वह भी 'अधिकार के स्पष्ट परित्याग' के कारण जैसा कि ऊपर देखा गया है। घटनाओं के सामान्य क्रम में यदि यह विशेष खंड 12 पक्षों के बीच अनुबंध में उपलब्ध नहीं था, तो मध्यस्थता खंड के दायरे और परिधि के कारण संपूर्ण विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता था और हमें उस तरह से मामले में गहराई से जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती जैसा हमने पहले किया है, लेकिन यह खंड 12 के समावेश के तथ्य और खंड 12 के अंतर्गत आने वाले दावे को वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक के अलावा किसी अन्य फोरम द्वारा न्यायनिर्णयन कराने के निर्णय के कारण इसके बाद के परित्याग के कारण है, हमारे पास भी इस निष्कर्ष के साथ अपनी सहमति दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए दीवानी वाद का विषय होने के नाते चौथे विवाद को भी मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। स्मरण रहे कि यह आदेश विवादित तथ्यों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और अपवादित मामलों से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि जैसा ऊपर दिया गया है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, हम इन अपीलों के इर्द-गिर्द केंद्रित विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के साथ अपनी सहमति दर्ज करना उचित समझते हैं। इसलिए अपीलें विफल होती हैं और खारिज की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

के.के.टी. अपीलें खारिज की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।